लोकतंत्र की आत्मा है - संवाद

हरियाणा संवाद

पाक्षिक : 1- 15 जून, 2023 www.haryanasamvad.gov.in अंक - 67

“ सच बोलने का यह फायदा होता है कि कभी कुछ याद रखने की जरुरत नहीं होती कि कब किसको क्या कहा था।
: अज्ञात

रेल व सड़क तंत्र से विकास की रफ़्तार
3

दक्षिणी हरियाणा में नहीं रहेगा जल संकट
6

सेहत को लेकर संजीदगी
8

डबल इंजन की सरकार विकास अपार

मनोज प्रभाकर

विकास एक सतत प्रक्रिया है। डबल इंजन की सरकार यानी केंद्र व राज्य में एक ही सियासी दल की सरकार। देश के राजनीतिक इतिहास में इस तरह की सरकारें पहले भी रही हैं, तो फिर पहले व आज मे फ़र्क क्या है ? फ़र्क साफ है, पहले केंद्र से एक रुपया चलता था, नीचे तक 25 पैसे पहुंचते थे, आज केंद्र से एक रुपया चलता है, नीचे तक पूरा एक रुपया ही पहुंचता है। न केवल पहुंचता है, अंत्योदय की भावना से उसका सदुपयोग भी होता है। पहले जन प्रतिनिधियों के मन में रुपए को हल्का करने की मंशा रहती थी, आज ऐसा नहीं है। सरकार की एक एक पाई के खर्च के लिए पुख्ता प्रबंधन किये गए हैं। इतना ही नहीं, खर्च और कार्य के लिए अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की गई है। निर्धारित बजट से कम खर्च होता है तो उस बचत की वापसी होती है, बंदरबांट नहीं होती। यही वजह है कि पूरी ईमानदारी व पारदर्शिता से देश प्रदेश का चौतरफा विकास हो रहा है।

केंद्र सरकार के वरहदस्त से हरियाणा में खूब विकास कार्य हुए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश का न केवल ढांचागत विकास कराया है बल्कि इसके प्रबंधकीय सॉफ्टवेयर को भी दुरुस्त करने का काम किया है। सॉफ्टवेयर पुराना होने व उसमें अनेक प्रकार के वायरस होने से लोगों के मन में सिस्टम के प्रति नाउम्मीदी हो चुकी थी। मनोहर लाल ने वर्ष 2014 में कुर्सी संभालते ही एलान कर दिया था कि वे सुशासन के लिए कोई समझौता नहीं करेंगे। तब से लेकर आज तक हर क्षेत्र में काम हुआ। एक समान हुआ और सबकी सहमति से हुआ। ईमानदारी का विशेष फायदा यह हुआ कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों का स्वमेव वर्धन होता चला गया। जहां भेदभाव नहीं होता वहां सवाल नहीं होते। जो होते हैं उनका अस्तित्व कमजोर होता है।

प्रदेश के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने व आम जन जीवन को सहज व सरल करने के लिए विगत नौ वर्षों में केंद्र व राज्य सरकार अनेक योजनाएं लेकर आईं। योजनाओं पर गंभीरता से कार्य हुए हैं। ग्रामीण विकास की खातिर कृषि एवं पशुपालन पर विशेष ध्यान दिया गया। ग्राम पंचायतों को सशक्त करने के लिए उनके अधिकारों का विस्तार किया गया व खर्च के अधिकार बढ़ाए गए। इतना ही नहीं पंचायती संस्थाओं में महिलाओं को 50 प्रतिशत की भागीदारी दी गई।

किसानों के सहयोग के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना व फसल बीमा योजना खूब काम कर रही हैं। हरियाणा सरकार ने तो बीज से बाजार तक किसानों का साथ देने की प्रतिबद्धता जताई है। फसल अवशेष प्रबंधन योजना रंग लाई है। अवशेषों का तोड़ निकला है तो पर्यावरण कई गुणा स्वच्छ हुआ है, जो पूरे जन जीवन के लिए सुकून वाली बात है। जल प्रबंधन के क्षेत्र में केंद्र व राज्य स्तर पर अनेक योजनाएं आई हैं जो स्थानीय लोगों के सहयोग से अपनी गति पर हैं। स्वच्छ भारत अभियान की योजनाओं ने तो पूरे देश का परिदृश्य ही बदल दिया है। खुले में शौचमुक्त प्रदेश में ठोस व तरल कचरा प्रबंधन की योजनाओं पर गंभीरता से कार्य चल रहा है। इन योजनाओं से मानो नई क्रांति का सूत्रपात हुआ है।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अलावा अनेक योजनाओं ने प्रदेश में महिला सशक्तिकरण को बल दिया है। छात्राओं की शिक्षा के लिए अनेक उल्लेखनीय कदम उठाए गए हैं।

सुशासन सहयोगियों की मदद से डिजिटलाइजेशन संबंधी अनेक योजनाएं संचालित हुई हैं जिनसे न केवल कामकाज में पारदर्शिता आई है, बल्कि अनावश्यक खर्चों पर रोक भी लगी है। इसके अलावा वर्ष 2022- 23 में जीएसटी संग्रह 30551 करोड़ रुपए हुआ है। 500 से ज्यादा सरकारी योजना, कार्यक्रम व सेवाओं के ऑनलाइन होने से लोगों का जेब खर्च काफी कम हुई है। खास पहलू यह है कि तकरीबन हर सिस्टम से बिचौलियों का खात्मा हो गया है। टेंडर कार्य ऑनलाइन होने से भ्रष्टाचार पर लगाम कसी गई है।

प्रधानमंत्री स्वामीत्व योजना ने प्राचीनकाल से चली आ रही समस्याओं का निदान किया है। प्रॉपर्टी विवाद निपटे हैं। प्रदेश के 6260 गांवों की 23,93,366 संपत्तियों के मालिकों को अधिकारिक हक प्रदान किया गया है। दीन दयाल जन आवास योजना के तहत 4692 एकड़ में कालोनियों को विकसित करने के लिए 457 लाइसेंस दिए गए हैं। आवास योजना के तत 13700 मकान बनाए हैं तथा 15649 निर्माणाधीन हैं।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 9,19 264 महिलाओं को मुफ़्त गैस कनेक्शन दिए गए। 'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड' के जरिए गरीब परिवारों के लोग कहीं से भी राशन प्राप्त कर रहे हैं। अन्न योजना के तहत एक करोड़ 38 लाख लाभार्थियों को मुफ़्त राशन दिया जा रहा है।

विद्युत आपूर्ति क्षेत्र में केंद्र के सहयोग से क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। बहुत पुरानी बात नहीं है, ग्राम्य जीवन में लोग तीन से सात दिन तक बिजली आने का इंतजार करते थे। एक दौर ऐसा आया कि तीन दिन में बिजली तो आने लगी लेकिन लोगों ने बिल अदा न करना अपनी शानो-शोकत समझना शुरू कर दिया। आज तस्वीर बदल चुकी है। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्र में न केवल 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो रही है बल्कि उपभोक्ता बिलों की अदायगी कर रिकार्ड बना रहे हैं।

प्रधानमंत्री जन धन योजना, मुद्रा योजना, जीवन सुरक्षा बीमा योजना के अलावा अनेक रोजगारपरक योजनाएं अपनी सफल राह पर हैं। शिक्षा, कौशल शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल एवं युवा विकास, शहरी स्थानीय निकाय, ऊर्जा, स्टार्ट अप, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, सिंचाई एवं जल संसाधन, आबकारी एवं काराधान, पर्यटन, कलां एवं संस्कृति, सिविल विमानन, उद्योग एवं वाणिज्य आदि अनेक ऐसी योजनाएं जमीन पर उतरी हैं जिन्होंने प्रदेश को समृद्ध करने का काम किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल व उनकी टीम के अथक प्रयासों से हुई प्रगति से सूबे के लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं।

नमो-मनो सरकार में हुआ चहुंमुखी विकास

पेज नं 4,5

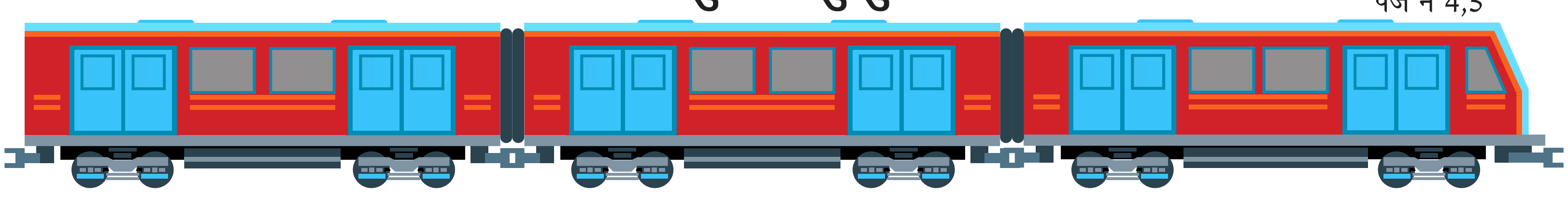

यूपीएससी परीक्षा में हरियाणा का दबदबा

संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने सिविल सेवा परीक्षा 2022 के नतीजे घोषित कर दिए। इस परीक्षा में हरियाणा के कई युवाओं ने उत्कृष्ट स्थान हासिल किया।

पूर्व डीजीपी मनोज यादव के बेटे अनिरुद्ध यादव ने 8वां रैंक हासिल किया। कैथल की कनिका गोयल ने 9वां रैंक हासिल किया। फतेहाबाद जिला गोरखपुर गांव के अभिनव सिवाच ने 12वां रैंक हासिल किया। जुलाना गुसाई खेड़ा गांव की अंकिता पंवार ने 28वां, झज्जर की मुस्कान डागर ने 72वां, चरखी दादरी के सुनील फोगाट ने 77वां, सोनीपत की निधि कौशिक ने 88वां, कैथल की दिव्यांशी सिंगला ने 95वां, पानीपत की मुस्कान खुराना ने 98वां रैंक, जींद खरैंटी गांव के अंकित नैन ने 99वां, महेंद्रगढ़ की दिव्या ने 105वां, कैथल गुलियाना निवासी हरदीप सिंह ने 227 वां, मेवात के आकिप ख़ान ने 268वां, तोशाम के भावेश ने 280वां, जींद शामदो गांव के मनीष ने 283वां, महेंद्रगढ़ की अभिरूचि यादव ने 317वां, भिवानी मितथाल गांव के राहुल ने 508वां और एचसीएस की सेकंड टॉपर प्रगति रानी ने 740वां रैंक हासिल किया।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने उम्मीद जताई कि जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं वे पूरी ईमानदारी और निष्ठा से राष्ट्र की सेवा करेंगे। प्रदेश के अन्य युवाओं से आह्वान किया कि वे इन मेहनती युवाओं से प्रेरणा लें और अपने जीवन के लक्ष्य को निर्धारत करते हुए आगे बढ़ें।

संपादकीय

नौ वर्ष में रचा नया इतिहास

अपने नौ वर्षों के ऐतिहासिक कार्यकाल में केंद्र में स्थापित मोदी सरकार ने, हरियाणा की विकास-गति को भी इस अवधि में एक अनूठी ऊर्जा प्रदान की है।

इस अवधि में जारी केंद्रीय योजनाओं का पूरा-पूरा लाभ हरियाणा को मिला। इसका एक कारण यह भी था कि सभी केंद्रीय योजनाओं को हरियाणा की मनोहर-सरकार ने पूरी तन्मयता और प्रतिबद्धता के साथ लागू भी किया।

जिस 'डबल इंजन सरकार' की चर्चा प्रायः सुनने में मिलती है, उसका एक आदर्श स्वरूप हरियाणा में मिला है। अपने नौ वर्ष के कार्यकाल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक अनूठे 'विज़न' के साथ 'सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास' के मूल मंत्र के साथ 'सर्वांगीण विकास' का भी एक दृष्टिकोण जोड़ा और उसके अद्भुत परिणाम देखने को मिले।

सबसे बड़ा वैशिष्ट्य यह रहा है कि पारदर्शिता व आधुनिक-तकनीक और एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) की नई टेक्नोलॉजी को भी सही ढंग से अपनाया गया। केंद्रीय योजनाओं पर पूर्ण अमल के साथ-साथ प्रदेश की अपनी योजनाएं भी सुचारू रूप से पूरी मुस्तैदी के साथ चलें, इसके लिए अधिकांश राजकीय-सेवाएं 'ऑनलाइन' उपलब्ध हैं। अब किसान के पास अपनी कृषि-भूमि का प्रामाणिक ब्यौरा उपलब्ध है। उसे अपनी फसल के बारे में भी पूरी-पूरी जानकारी है। सभी प्रकार के केंद्रीय-अनुदान एवं सहायता राशि आम आदमी के खाते में सीधे रूप में पहुंच रही है। क्रियान्वयन में किसी मध्यस्थ की कोई भूमिका न रहे, यह भी सुनिश्चित बनाया जा रहा है और इसी रास्ते पर सभी पक्ष चलते रहे हैं। 'सीएम-विंडो', 'सीएम-उड़नदस्ते' और अब 'जन संवाद' के माध्यम से प्रदेश के प्रधानसेवक के रूप में स्वयं मुख्यमंत्री सीधे रूप में सामान्यजन को उपलब्ध हो रहे हैं।

इन नौ वर्षों में विकास का एक नया इतिहास लिखा गया है। इसी नव-इतिहास लेखन में जितनी महत्वपूर्ण भूमिका केंद्रीय व प्रादेशिक नेतृत्व की है, उतनी ही सरकारी तंत्र में पूरी क्षमता व समर्पण भाव से लगे हुए कर्मियों व अधिकारियों की है। यह एहसास ही संतोषप्रद है कि प्रदेश का जन-जन अपने आपको सुरक्षित हाथों में महसूस करने लगा है।

-सलाहकार संपादक

आत्मनिर्भर होंगे दिव्यांग

हरियाणा में जल्द ही करीब 35 हजार दिव्यांगों को रोजगार मिलने जा रहा है। इनमें से 15 हजार सरकारी क्षेत्र में जबकि 20 हजार दिव्यांग निजी क्षेत्र में समायोजित किए जाएंगे।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री ओमप्रकाश यादव की उपस्थिति में 'यूथ फॉर जॉब' कंपनी और राज्य सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इस एमओयू से प्रदेश में निर्धारित कौशल के अनुसार 7,000 दिव्यांगजनों की भर्ती प्रक्रिया में तेजी आएगी।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से जल्द ही 80 फीसदी या इससे अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांगजनों को 400 मोटराइज्ड वाहन वितरित किए जाएंगे। इससे उन्हें आने-जाने में आसानी होगी और वे आत्मनिर्भर होंगे।

राज्यमंत्री ने बताया कि इससे पहले, ई-कॉमर्स क्षेत्र की जानी-मानी कंपनी अमेजॉन के साथ भी एक एमओयू साइन किया गया है। इस कंपनी के माध्यम से हरियाणा के करीब 10 हजार दिव्यांगजनों को उनकी कार्य क्षमता के अनुसार रोजगार दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिव्यांगों के हितों की रक्षा को लेकर अत्यंत गंभीर हैं। वे चाहते है कि राज्य के अधिक से अधिक दिव्यांगों को उनके कौशल और शारीरिक क्षमता के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए।

उन्होंने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री ने सरकारी नौकरियों में एक जनवरी,1996 से लेकर आज तक का सारा बैकलॉग जल्द से जल्द भरने के निर्देश दिए हैं।

हरियाणा दिव्यांगजन आयुक्त राजकुमार मक्कड़ ने बताया कि दिव्यांगों के बैकलॉग में से करीब 4000 पदों पर पात्र दिव्यांगों की भर्ती कर ली गई है और शेष की प्रि' या जारी है। हरियाणा ही नहीं देश के इतिहास में पहली बार किसी एक राज्य द्वारा 103 पैरा -डॉक्टर तथा 2500 पैरा-मेडिकल स्टाफ की भर्ती की गई है।

उन्होंने बताया कि एचसीएस की भर्ती में भी 14 वैकेंसी का बैकलॉग भरा जाएगा। इसके लिए विज्ञापन को संशोधित करके दिव्यांगजनों के लिए कोटा निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, पीजीटी तथा कौशल रोजगार निगम के तहत निकाली जा रही रिक्तियों में भी दिव्यांगजनों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया जा रहा है।

बौनों और किन्नरों को भी मिलेगी 2750 रुपए पेंशन

हरियाणा सरकार ने बौनों और किन्नरों का भत्ता बढ़ाकर 2750 रुपये मासिक कर दिया है। बढ़ा हुआ भत्ता एक अप्रैल, 2023 से लागू होगा।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री ओम प्रकाश यादव ने बताया कि इन दोनों योजना के तहत भत्ता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति हरियाणा का अधिवासी होना चाहिए और उसकी आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। बौना भत्ता के लिए पुरुष का कद 3 फुट 8 इंच और महिला का कद 3 फुट 3 या इससे कम होना चाहिए। दोनों श्रेणियों के तहत भत्ता प्राप्त करने के लिए आवेदक को सिविल सर्जन से सर्टिफिकेट भी प्रस्तुत करना होगा।

उन्होंने बताया कि जम्मू एवं कश्मीर से विस्थापित होकर हरियाणा आने वाले कश्मीरी परिवारों की सहायता राशि बढ़ाकर 1250 रुपए प्रतिमाह प्रति सदस्य की गई है परन्तु यह राशि प्रति परिवार 6250 प्रतिमाह से अधिक नहीं होगी।

महाशय का परलोक गमन

हरियाणवी गायकी के महाशय कहे जाने वाले पालेराम दहिया की जीवन यात्रा पूरी हुई। अड़सठ वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उनके निधन से हरियाणवी संस्कृति को अपूर्णिय क्षति हुई है। अक्सर गंभीर मुद्रा में दिखाई देने वाले पालेराम हमेशा अपनी गायकी के जरिए लोगों का भरपूर मनोरंजन करते रहे।

सोनीपत के गांव हलालपुर में उनका जन्म हुआ था। उन्हें बचपन से ही गाने का चस्का था। गांव गांधरा के बलबीर सिंह को वे अपना गुरु मानते थे। 1975-76 में उन्होंने अपनी भजन पार्टी बनाई। उस वक्त पार्टी में दो घड़वे व एक बैन्जू वादक होते थे। धीरे धीरे घड़वे बजाने वालों की संख्या पांच हो गई व एक हारमोनियम वादक शामिल हो गया था।

पालेराम दहिया, मशहूर गायक राजकिशन अगुवानपुरिया व मास्टर सतबीर से पहले के गायक थे। उन्हें सैकड़ों रागनी व भजन कंठस्थ थे। उन्होंने कागज पर लिखा कभी नहीं गाया, यादाश्त गजब की थी। वे हर मौके पर गाते थे, विशेषता यह थी कि उन्होंने कभी गलत शब्दावली का सहारा नहीं लिया। जो भी गाया सामाजिक लिहाज पर खरा होकर गाया। इतना ही नहीं उन्होंने अपने गायन व चुटकुलों से सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करने का भी काम किया। विख्यात कवि मेहर सिंह व दादा लख्मीचंद के किस्सों से ली गई रागणियों पर ज्यादा फोकस रहा। इनके अलावा बाजे भगत व मांगेराम की गढ़ी कविताई पर भी गायन किया।

रागणियों के कम्पीटिशन में उनका खूब सिक्का चलता था। गायक मा. सतबीर के साथ जब उनका मुकाबला होता था तो सुनने वालों की भारी भीड़ उमड़ती थी। एक समय में उनके गीत 'गिन के दे लिए बोल 360 चोबारे आली..' ने धूम मचाई थी। इसके अलावा हे मानव शुभ कर्म करा कर, गंगा जी तेरे खेत में भजन भी काफी लोकप्रिय रहे।

सलाहकार संपादक : डा. चंद्र त्रिखा
सह संपादक : मनोज प्रभाकर
स्टाफ राइटर : संगीता शर्मा
संपादन सहायक : सुरेंद्र बांसल
चित्रांकन एवं डिज़ाइन : गुरप्रीत सिंह
डिजिटल सपोर्ट : विकास डांगी

स्मार्ट मीटर से मिलेगी स्मार्ट बिजली

गुरुग्राम, फरीदाबाद, करनाल व पानीपत में स्मार्ट मीटर लगने शुरु हो गए हैं। अब तक सात लाख मीटर लगाए जा चुके हैं। स्मार्ट मीटर बहुत ही उपयोगी बताए जाते हैं, इन्हें कभी भी चेक किया जा सकता है कि बिजली की कितनी खपत हुई। घर से बाहर जाते समय इन्हें बंद भी किया जा सकता है। इससे उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की शंका भी नहीं रहेगी। राज्य सरकार ने आमजन से आह्वान किया है कि वे बिजली जरूरत के मुताबिक ही उपयोग करें ताकि ऊर्जा संरक्षित की जा सके।

प्रदेश में बिजली आपूर्ति की स्थित बहुत अच्छी है। वर्तमान में, 9500 हजार मेगावाट प्रतिदिन की बिजली की खपत है, जिसे प्रदेश के बिजली निगमों द्वारा पूरा किया जा रहा है। पिछले वर्ष में अधिकतम बिजली की खपत 12 हजार 185 मेगावाट थी, जून और जुलाई माह सबसे अधिक गर्मी का प्रभाव होता है और फसलों में भी पानी की जरूरत बढ़ जाती है, उन दिनों में 12 हजार मेगावाट प्रतिदिन की बिजली की खपत होती है।

खेदड़ के दोनों यूनिट से 1200 मेगावाट

बिजली, यमुनानगर के दोनों यूनिट से 700 मेगावाट, पानीपत के तीन यूनिट में से दो चल रहे हैं तथा एक यूनिट में तकनीकी खामी है जिसे जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा, प्रदेश को केंद्र सरकार से भी बिजली मिल रही है।

सरकार द्वारा ट्यूबवेल पर करीब 5800 करोड़ रुपये खर्च किया जाता है, जिसमें किसान के हिस्से में बहुत ही कम जाता है, शेष राशि सरकार द्वारा सब्सिडी के तौर पर खर्च की जाती है। इसके अलावा केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक व उड़ीसा में समय पर बारिश आने से वहां के नेशनल ग्रिड से आसानी से बिजली मिल जाती है। सरकार को सात से आठ रुपए प्रति यूनिट खर्च आता है लेकिन सरकार किसानों से 10 पैसे प्रति यूनिट ट्यूबवेल की बिजली का बिल ले रही है।

बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार ने हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी) की सिफारिश को खारिज करते हुए किसानों के बिजली चोरी जुर्माने में वृद्धि के आदेश को रद्द कर दिया है। इस संबंध में प्रदेश सरकार द्वारा पुरानी पॉलिसी के अनुसार ही कार्य किया जाएगा। पुराने नियम के अनुसार एक मेगावाट पर 2,000 रुपए तथा इससे अधिक 10 मेगावाट तक 20,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान था और अब भी पुराने नियम प्रदेश में लागू रहेंगे। सरकार द्वारा पुराने आदेशों को वापस लिया गया है।

फिरोजपुर झिरका उपमंडल के 80 गांवों को पेयजल आपूर्ति प्रदान करने के लिए रैनीवेल परियोजना पूर्ण हो चुकी है। इस परियोजना पर लगभग 210 करोड़ रुपए की लागत आई है।

महेंद्रगढ़ के बालखी में 114 करोड़ रुपए की लागत से पानी आपूर्ति प्रणाली में सुधार का कार्य जुलाई तक पूरा कर लिया जाएगा।

रेल व सड़क तंत्र से विकास की रफ़्तार

विशेष प्रतिनिधि

हरियाणा प्रदेश सड़क, रेल व हवाई तंत्र को सुदृढ़ करने में आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के अथक प्रयासों से केंद्र सरकार ने हरियाणा की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को त्वरित स्वीकृति प्रदान की हैं और अनेक परियोजनाएं इस कार्यकाल में पूरी भी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कई केंद्रीय मंत्रियों ने स्वयं हरियाणा आकर कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। भारतमाला परियोजना के तहत भी प्रदेश में कई नये हाई-वे का काम प्रगति पर है और अब तो प्रदेश के कई शहर पांच-पांच नेशनल हाई-वे से जुड़ गए हैं, जिससे न केवल लोगों को आवागमन की सुविधा मिली है, बल्कि औद्योगिक विकास के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मज़बूती मिली है।

हाल ही में हरियाणा को द्वारका एक्सप्रेस-वे के रूप में एक और एक्सप्रेस-वे का तोहफ़ा मिला है। 9,000 करोड़ रुपए की लागत का 29.6 किलोमीटर लंबाई वाला द्वारका एक्सप्रेस-वे देश का पहला एलिवेटेड 8-लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेस-वे है, जिसमें 18.9 किमी हिस्सा हरियाणा क्षेत्र में पड़ता है। निश्चित ही हरियाणावासियों को इसका बहुत लाभ मिलेगा। विशेष रूप से गुरुग्राम को जाम से मुक्ति मिलेगी।

हरियाणा में यातायात सुगम

दिल्ली व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यातायात अवरूद्धता से मुख्यमंत्री भली-भांति परिचित थे और उन्होंने वर्ष 2014 में सत्ता संभालते ही लोगों को इस समस्या से निजात दिलाने की ठान ली थी। सर्वप्रथम उन्होंने हरियाणा के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेस-वे, जो लंबे अरसे से राजनीतिक विवादों के कारण सिरे चढ़ नहीं पा रही थी, को न केवल पूरा करवाया बल्कि इसे फोर लेन से छह लेन का करवाया। साथ ही केंद्र सरकार से इस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे के कार्य को भी पूरा करने का आग्रह किया जो सफल रहा। फलस्वरूप दिल्ली से आगे जाने वाले यात्रियों व माल वाहक वाहनों का आवागमन सुगम हुआ।

मेट्रो व रेल इंफ्रास्ट्र• र मज़बूत

दिल्ली मेट्रो को गुरुग्राम, बल्लभगढ़ तक विस्तारित किया और अब गुरुग्राम से फरीदाबाद के बीच भी मेट्रो प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री के प्रयासों से तैयार किया गया है, जो आगामी दो वर्षों में पूरा हो जाएगा। इसके अलावा, पलवल से सोनीपत तक रेलवे इंफ्रास्ट्र• र को मज़बूती प्रदान करने की मुख्यमंत्री की सोच के अनुरूप हरियाणा ओर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना अस्तित्व में आई। इसके तहत मानेसर से पाटली तक प्राथमिकता खंड का निर्माण कार्य लगभग 176 करोड़ रुपए की लागत से प्रगति पर है और वर्ष 2024 तक पूरा होने का अनुमान है।

मुख्यमंत्री की पहल पर हरियाणा ने रेलवे परियोजनाओं को तीव्र गति प्रदान करने हेतु रेलवे मंत्रालय के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्र• र डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का गठन किया गया। इसके तहत रेलवे स्टेशनों का नवीनीकरण, रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण सहित राज्य को मैन्युअल फाटक से मुक्त बनाने जैसे कार्य किये जा रहे हैं। इसके लिए अक्तूबर, 2014 से नवंबर, 2022 तक 104 आर.ओ.बी. और आरयूबी का कार्य शुरू किया गया, जिनमें से 58 आरओबी और आरयूबी का कार्य पूरा हो चुका है तथा 46 का कार्य प्रगति पर है। जबकि वर्ष 2023-24 के बजट अभिभाषण में मुख्यमंत्री ने 36 आरओबी और आरयूबी के निर्माण का लक्ष्य रखा है।

रोहतक व कुरुक्षेत्र में रेलवे बाईपास

रोहतक में एलिवेटड रेलवे लाइन परियोजना पूरी होने से जिला को रेलवे बाईपास का तोहफ़ा मिला है। कुरुक्षेत्र में भी एलिवेटड रेलवे लाइन परियोजना का कार्य शुरू हुआ है जिसकी इस वर्ष के अंत तक पूरा होने की संभावना है। राज्य सरकार ने बहादुरगढ़ और कैथल में भी एलिवेटेड रेलवे लाइन की परियोजना बनाई है।

सड़कों के सुधार का लक्ष्य

वर्तमान राज्य सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान लगभग 2,300 करोड़ रुपए से अधिक की राशि से 5,460 से अधिक किलोमीटर लंबी नई सड़कों का निर्माण किया है। इतना ही नहीं, वर्ष 2022-23 के दौरान 311 किलोमीटर से अधिक नई सड़कों का निर्माण और 2,954 किलोमीटर सड़कों का सुधार किया गया। जबकि वर्ष 2023-24 में 5,000 किलोमीटर सड़कों के सुधार का लक्ष्य रखा है। साथ ही, भीड़ कम करने और सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए सरकार 14 नए बाइपास का निर्माण भी शुरू करेगी।

हवाई तंत्र के संचालन पर ज़ोर

विगत साढ़े आठ वर्षों में हरियाणा सरकार ने हवाई तंत्र के संचालन पर भी ज़ोर दिया है। हिसार हवाई अड्डे को एविएशन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसका कार्य तेज़ गति से चल रहा है। करनाल हवाई अड्डे को भी विस्तारित किया जाएगा, जिसके लिए भूमि से संबंधित प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं और इसी वर्ष कार्य शुरू होने की संभावना है। भिवानी व बाछोद नारनौल हवाई पट्टियों के भी विस्तार करने की योजना है। इतना ही नहीं, गुरुग्राम में हेली-हब शुरू करने का भी प्रस्ताव है, जिसका उद्देश्य हेलीकॉप्टरों के रख-रखाव, मरम्मत और ओवरहॉलिंग की सुविधा प्रदान करना है।

बिजली चोरी के जुर्माने से राहत

सस्ती बिजली का फायदा उठाएं किसान

बिजली निगमों द्वारा किसानों पर कृषि क्षेत्र में बिजली चोरी पर लगाए जाने वाले जुर्माना सर्कुलर को वापिस ले लिया है। यह सर्कुलर एचईआरसी द्वारा की गई सिफारिश पर जारी किया गया था।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पत्रकार सम्मेलन में कहा कि निगमों द्वारा जारी इस सर्कुलर से किसानों पर बड़ा जुर्माना तय हो रहा था। सर्कुलर में जुर्माने की राशि छह लाख रुपए तक बना दी गई थी। जबकि पहले किसी किसान का यदि कोई डिफॉल्ट मिलता था तो उस पर 2,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक जुर्माना लगता था। लगभग 6 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि सरकार द्वारा बिजली निगमों को कृषि क्षेत्र की फीडरों में सुधार के लिए दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों से 10 पैसे प्रति युनिट ट्यूबवैल की बिजली का बिल ले रही है, लेकिन अधिक जुर्माना लगाना ठीक नहीं है।

मुख्यमंत्री ने किसानों से आह्वान किया है कि वे बिजली चोरी न करें। सरकार ने घरेलू व औद्योगिक बिजली के इन्फ्रास्ट्र• र में सुधार किया है। इसके अलावा वर्ष 2014 में जो लाईन लोस 34 प्रतिशत था वह घटकर 11 प्रतिशत हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 61,500 नए ट्यूबवैल बिजली कनेक्शन जारी किए हैं। कुसुम योजना के तहत भी 50 हजार से अधिक सोलर बिजली कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।

अंत्योदय परिवार, जिनकी सालाना आय एक लाख रुपए से कम है और बिजली बिलों की बकाया राशि के कारण उनके बिजली के कनेक्शन कट चुके हैं, ऐसे परिवारों की बकाया राशि को माफ करके उन्हें बिजली के कनेक्शन तुरंत दिए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि ऐसे अंत्योदय परिवारों के बकाया बिजली बिलों की मूल राशि का 50 प्रतिशत या अधिकतम 1 साल का औसतन बिजली बिल, जो भी कम हो, उतनी राशि उनसे ली जाएगी। उदाहरण के तौर पर यदि किसी परिवार का औसतन सालाना बिजली बिल 8,000 या 10,000 रुपए बनता है और उनकी कुल बकाया राशि 6,000 रुपए है, तो इस 6,000 रुपए की राशि में से 3,000 रुपए की राशि ही ऐसे परिवारों से ली जाएगी और यदि किसी का बिल 20,000 से ज़्यादा है तो 1 साल का 10,000 रुपए वही राशि ली जाएगी। इस राशि को भी किस्तों में अगले बिलों में जोड़ कर लिया जाएगा। इस बारे में कुछ किसानों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि बिजली की दरें बहुत कम हैं। चोरी न करें तो काम चल जाता है। चोरी करने से बेवजह बदनामी होती है।

-संवाद ब्यूरो

बाढ़डा विधानसभा क्षेत्र में 35 गांवों की नहरी आधारित पेयजल आपूर्ति योजना तथा नगीना व पिंगवान ब्लॉक के 52 गांवों व 5 ढाणियों को जलापूर्ति प्रणाली में सुधार कार्य इस वर्ष के अंत तक पूरे कर लिए जाएंगे।

139 करोड़ रुपए की लागत से पिंजौर में बन रही सेब, फल व सब्जी मंडी का कार्य अंतिम चरण में है। 52 दुकानों में से 39 का आवंटन किया जा चुका है, शेष दुकानों की आवंटन प्रकिया चल रही है।

नमो-मनो सरकार में

कृषि एवं किसान कल्याण

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना : प्रदेश के 26 लाख 50 हजार किसानों को 5,983 करोड़ रुपए की राशि मुआवजे के रूप में दी।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनाः प्रदेश के 19.82 लाख किसानों को 13 किस्तों में 4,287 करोड़ रुपए की राशि दी गई।

फसल अवशेष प्रबंधन योजना : पराली खरीदने व उद्योगों तक पहुंचाने के लिए नया पोर्टल बनाया गया है। इस पर पराली खरीदने वाले ठेकेदारों व उद्योगों की जानकारी भी उपलब्ध होगी जो किसान अपनी पराली बेचना चाहता है तो वह पोर्टल के माध्यम से सीधा सम्पर्क कर सकता है। हरेडा द्वारा फसल अवशेष/पराली आधारित परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य में फसल अवशेष आधारित 654 मेगावाट क्षमता की छह परियोजनाएं कार्यरत हैं। इसके अलावा 198 मेगावाट क्षमता की 2 परियोजनाएं फरीदाबाद व जींद में चालू वर्ष में आरंभ हो जाएंगी। वर्ष 2022-23 के दौरान इन परियोजनाओं में 5 लाख 9 हजार टन पराली को उपयोग किया गया। वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य में स्थापित बायोमास विद्युत उत्पादन, एथेनोल प्लांट एवं उद्योगों में लगभग 13 लाख 14 हजार 850 टन फसल अवशेष/पराली उपयोग की जाएगी।

कृषि यंत्रः प्रदेश में 472 मशीनरी बैंक स्थापित किए गए व किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर कुल 315 करोड़ 19 लाख रुपए अनुदान दिया।

सॉयल हैल्थ कार्ड योजना : किसानों को लगभग 87 लाख सॉयल हैल्थ कार्ड वितरित किए गए।

अटल भूजल योजनाः योजना की अवधि 2019 से 2025 है। भूजल स्तर के मापन हेतु 1,000 पीजोमीटर के निर्माण और पीजोमीटर पर डीडब्ल्यूएलआर सैनसर लगाने का कार्य प्रगति पर है। 1,669 रेन गेज लगाए गए है। 1,669 भूजल स्तर संकेतक की सप्लाई 1,669 ग्राम पंचायतों में की गई है और इनका प्रयोग किया जा रहा है। 1,669 जल गुणवत्ता परीक्षण किट की सप्लाई 1,669 ग्राम पंचायतों में की गई है जिनसे पानी का परीक्षण प्रगति पर है। योजना के तहत सभी ग्राम पंचायतों में जल सुरक्षा योजनाएं तैयार की गई हैं।

राष्ट्रीय मधुमक्खी पालनः मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए मधुमक्खी के बक्से की खरीद पर 85 प्रतिशत और उपकरण की खरीद पर 75 प्रतिशत सहायता, शहद प्रसंस्करण, बॉटलिंग और शहद परीक्षण का प्रावधान किया गया। शहद उत्पादन के लिए 70,834 बक्से उपलब्ध करवाए गए। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन के तहत 20.56 करोड़ रुपए की राशि विभिन्न मदों में अनुदान स्वरूप दी जाएगी तथा 20 करोड़ रुपए की लागत से एक क्वालिटी कंट्रोल लैब स्थापित की जा रही है।

राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टलः 108 मंडियों को इस प्लेटफार्म से जोड़ दिया गया है। 82 लाख 52 हजार किसानों ने 76,530 करोड़ 47 लाख रुपये की फसल बेची है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनाः इसके अंतर्गत मिट्टी संरक्षण, प्राकृतिक वनस्पति के उत्थान व भूजल के पुनर्भरण से संबंधित कार्य मुख्यतः किये जाते है। इस योजना के तहत कुल 165.48 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त वाटरशैड स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में कुल नौ केंद्रीय प्रयोजित परियोजनाएं जिनका बजट कुल 80.59 करोड़ रुपए के लगभग है को भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की है। यह योजना राज्य के पांच जिलों नामतः भिवानी, चरखीदादरी, गुरुग्राम, महेन्द्रगढ़ व यमुनानगर में अगामी पांच वर्षों में क्रियान्वित की जाएगी।

जल क्रांति अभियान योजना : अंबाला जिला के नहरी क्षेत्र को मॉडल कमाण्ड क्षेत्र में बदलने के लिए 1000 हैक्टेयर क्षेत्र को चयनित किया गया है जिसकी कुल लागत 7 करोड़ 71 लाख रुपए है व 12 गांव के किसानों को इस योजना का लाभ होगा। सभी 8 परियोजनाओं का कार्य पूरा हो चुका है।

पशुधन सुरक्षा योजनाः पंडित दीन दयाल उपाध्याय योजन के तहत 8.52 लाख पशुओं का बीमा कराया गया। इसके अलावा 3.90 लाख पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान किया गया। एक लाख 54 हजार पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये गए हैं।

जन-स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी

जल जीवन मिशन : ग्रामीण क्षेत्रों में 17 लाख 66 हजार 363 जल कनैक्शन दिये गए हैं।

रोज़गार

राष्ट्रीय कैरियर सेवा परियोजना : इसके अंतर्गत मॉडल कैरियर सेंटर, हिसार व रोहतक की स्थापना की गई है, इन सेंटरों के माध्यम से अब तक 184 रोजगार मेले आयोजित किए गए हैं जिसमें 2,598 नियुक्तियां निजी क्षेत्र में करवाई गई हैं।

भवन एवं सड़कें

सेतु भारतम योजना सड़क सुरक्षा के महत्व की ओर ध्यान देने के साथ शुरू की गई। पहल का उद्देश्य उचित योजना और कार्यान्वयन के साथ मजबूत बुनियादी ढांचे का विकास करना है। इस परियोजना का लक्ष्य पुराने और असुरक्षित पुलों के नवीनीकरण के साथ-साथ नए पुलों का निर्माण करना है। योजना के तहत 10 आर.ओ.बी प्रायोजित थे। 346 करोड़ 69 लाख रुपए की लागत से आठ पुलों का निर्माण किया जाएगा। 4 आर.ओ.बी का कार्य प्रगति पर है तथा दो का कार्य पूर्ण हो चुका है।

पर्यटन

स्वदेश दर्शन योजना : 97 करोड़ 34 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई, जिसमें से 77 करोड़ 87 लाख रुपए की राशि जारी तथा कार्य पूर्ण चरण में है। इसके अतिरिक्त कृष्णा सर्किट परियोजना-द्वितीय की 97.06 करोड़ रुपए की डीपीआर केंद्र सरकार को स्वीकृति हेतु भेजी जा चुकी है।

स्वर्ण जयंती गुरु दर्शन यात्रा योजना : श्री हजूर साहिब गुरुद्वारा, श्री ननकाना साहिब, श्री हेमकुण्ड साहिब और श्री पटना साहिब जाने वाले प्रदेश के तीर्थ यात्रियों के लिए भी वितीय सहायता उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से स्वर्ण जयंती गुरु दर्शन यात्रा योजना शुरू की गई है।

ग्रामीण विकास

हरियाणा देश का पहला राज्य, जिसके सभी ग्रामीण व शहरी क्षेत्र खुले में शौच से मुक्त घोषित किये गये। गांवों व शहरों में 7 लाख 76 हजार से अधिक शौचालय बनाए गए। अब हरियाणा ओडीएफ प्लस की ओर अग्रसर है। अब तक गांवों में 5,912 ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन के प्रोजेक्ट मंजूर किए जा चुके हैं।

दीन दयाल उपाध्याय कौशल योजनाः इसके अंतर्गत 178.99 करोड़ रुपए की राशि से 39,468 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण): इसके तहत 22 हजार 844 मकान बनाए गए।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशनः तीन चरणों में 10 चयनित समूहों के 150 गांवों की पहचान की गई। इस योजना के अंतर्गत अब तक 634 करोड़ 82 लाख रुपए की लागत से 1,229 कार्य पूरे किए गए।

महिला एवं बाल विकास

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम : जन्म के समय लिंगानुपात की दर सुधरकर 927 हो गई है।

सुकन्या समृद्धि खाता योजनाः प्रधानमंत्री द्वारा 22 जनवरी 2015 को पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर 'सकुन्या समृद्धि योजना' की शुरुआत की गई। डाकघरों में 6,95,717 खाते खोले जा चुके हैं।

राष्ट्रीय पोषाहार मिशन : राष्ट्रीय पोषाहार मिशन के तहत 6,11,180 सामुदायिक आधारित कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। 3,02,965 ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण दिवस का आयोजन किया गया है। ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइसेस (इन्फैंटोमीटर, स्टैडोमीटर, मदर एंड चाइल्ड वेटिंग स्केल, इन्फैंट-वेटिंग स्केल) सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में 2019- 2020 में वितरित किये गये। कुल 13931 आंगनवाड़ी केंद्रों को किचन गार्डन के तहत कवर किया गया है।

वन स्टॉप सैंटर सखी : सभी जिलों में वन स्टाप सेंटर सखी स्थापित कर दिए गए हैं।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना : लगभग 8 लाख महिलाओं को कवर किया गया है।

शहरी स्थानीय निकाय

अटल नवीकरण मिशन-अमृत

यह मिशन 20 शहरों में लागू किया जा चुका है। इन शहरों के लिए 2,565 करोड़ 74 लाख रुपए की लागत की 48 परियोजना रिपोर्ट स्वीकृत की जा चुकी हैं।

स्मार्ट सिटी योजना : वर्ष 2015 स्मार्ट सिटी योजना के तहत फरीदाबाद में 930 करोड़ 4 लाख रुपए की लागत से 45 परियोजनाओं पर एवं करनाल में 1,004 करोड़ 97 लाख रुपए की लागत से 94 परियोजनाओं पर कार्य जारी है।

प्रधानमंत्री आवास योजना : शहरी वर्ष 2015 अब तक लगभग 13,700 मकान बनाए गए तथा 15,649 घर निर्माणाधीन हैं।

करनाल के कुटेल में बन रहे पंडित दीन दयाल उपाध्याय युनिवर्सिटी ऑफ़ हेल्थ साइंसेस का काम प्रक्रियाधीन है। इसी साल के अंत तक ओपीडी सेवाएं शुरू करने की तैयारी है।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विभिन्न विभागों की 100 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की मॉनिटरिंग हेतु हरियाणा प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल लॉन्च किया है।

हुआ चहुंमुखी विकास

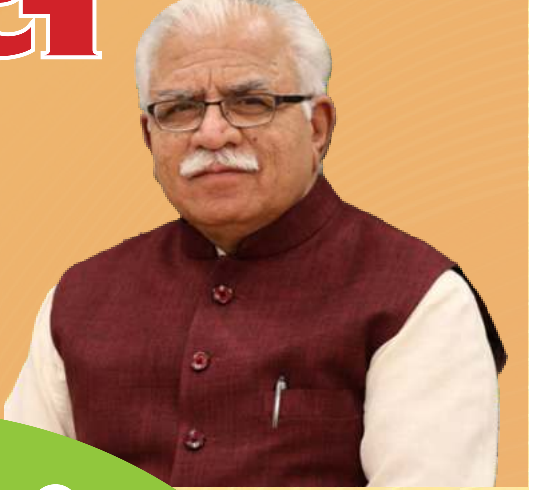

उद्योग एवं वाणिज्य

स्टार्टअप इंडिया स्कीम

देश के नागरिकों के बीच उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत की गयी है। इस योजना के अंतर्गत रोजगार व उद्योग के लिए फंडिंग सहायता, मार्गदर्शन और उद्योग भागीदारी के अवसर प्रदान करके भारत में स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। हरियाणा में स्टार्टअप इंडिया पहल के अंतर्गत युवा वर्ग स्टार्टअप में पंजीकरण करके स्वयं रोजगार के साथ-साथ दूसरों को रोजगार प्रदान कर रहे हैं। हरियाणा में 4,119 युवा स्टार्टअप्स का पंजीकरण हो चुका है।

आबकारी एवं कराधान

गुड्स सर्विस टैक्स (जी.एस.टी): जीएसटी संग्रहण में हरियाणा देश में छठे स्थान पर है।

ई-वे बिल स्कीम : अब तक 32 करोड़ 47 लाख से अधिक ई-वे बिल जनरेट किए गए हैं।

उजाला योजना : 2.15 करोड़ एलईडी बल्ब बांटने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। एक करोड़ 56 लाख एलईडी बल्ब, 2 लाख 13 हजार एलईडी ट्यूब तथा 60 हजार 709 पंखे वितरित किये जा चुके है, जिनसे 411 मेगावाट ऊर्जा की वार्षिक बचत हुई है।

लघु खेल केंद्र योजना : इस योजना के तहत जिला स्तर पर 10 लघु खेल केंद्र खोले गए हैं। मैदानों के रख-रखाव, खेल उपकरण व खेल किट आदि के लिए खेल केंद्रों को एकमुश्त पांच लाख रुपए की राशि देने का प्रावधान है। इन खेल केंद्रों को 35 लाख रुपए की राशि जारी की जा चुकी है।

प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना : 6,260 गांवों की 23,93,366 सम्पतियों के भू-स्वामियों को पंजीकृत टाईटल डीड वितरित कर दी गई है।

स्वास्थ्य सेवाएं

मिशन इंद्रधनुष : 3 लाख 32 हजार 975 गर्भवती महिलाओं तथा 12 लाख 38 हजार 59 बच्चों का टीकाकरण किया गया।

सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम : सार्वभौमिक टीकाकरण औसतन 91 प्रतिशत रहा।

मिजेल रुबैला अभियान : 79 लाख 38 हजार बच्चों के टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिसमें 78 लाख 72 हजार बच्चों का टीकाकरण किया गया।

ई-संजीवनी : यह सुविधा सभी जिलों में शुरू की गई है और अब तक 4 लाख रोगियों का ईलाज इसके माध्यम से किया गया है।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस : वर्ष 2015 से प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है।

आयुष्मान भारत : हरियाणा में 15 लाख 50 हजार परिवार लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। हरियाणा इस योजना के तहत पहले क्लेम की अदायगी करने वाला देश का पहला राज्य है। राज्य के 728 अस्पतालों को पैनल पर रखा गया है, जिनमें 176 सरकारी और 552 प्राइवेट अस्पताल हैं। लगभग 29 लाख गोल्डन कार्ड बनाए व 5 लाख 69 हजार रोगियों का 613.66 करोड़ रुपए से मुफ्त ईलाज किया गया।

आयुष हैल्थ वेलनेस सेंटर : 431 आयुर्वेदिक औषधालयों व 138 उप स्वास्थ्य केंद्रों को आयुष हैल्थ वेलनेस सेंटर बनाने का निर्णय लिया, जिसमें से 347 को अपग्रेड किया जा चुका है।

संस्थागत वित्त एवं ऋण नियंत्रण

प्रधानमंत्री जन धन योजना : 89 लाख 85 हजार बैंक खाते खोले गये हैं।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना : 24 लाख 43 हजार लोगों को 23 हजार 967 करोड़ रुपए के ऋण दिए गए हैं।

प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना : इस योजना के तहत 78 लाख 84 हजार लोगों का पंजीकरण किया गया है।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना : 30 लाख 18 हजार लागों का पंजीकरण किया गया है।

अटल पेंशन योजनाः 9 लाख 88 हजार लोगों का पंजीकरण किया गया है।

स्टैंड-अप इंडिया स्कीम : 4 हजार 987 लोगों को 1006 करोड़ रुपए के ऋण दिए गए।

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना : 46,616 रेहड़ी और फड़ी लगाने वालों को अपना काम शुरु करने के लिए 10 हजार रुपए तक ऋण की सुविधा दी गई है।

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना

आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म खाद्य उद्योग के विकास के लिए यह योजना शुरु की गयी है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता बीमा योजनाः 10,030 लाभपात्रों को 75 करोड़ 64 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई।

गौशालाओं के लिए बजट

प्रदेश की गौशालाओं को गौशाला एवं गौसदन योजना के अन्तर्गत वितीय वर्ष 2023-24 के लिए मौसमी सूखा चारा (तूढ़ा / भूसा) खरीद के लिए त्वरित चारा अनुदान की किस्त जारी की गई हैं। राज्य की कुल 546 पंजीकृत गौशालाओं को 35 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। गौशालाओं का बजट 40 से किया 400 करोड़ किया है। दलाल ने बताया कि जिला भिवानी की 36 गौशालाओं के लिए दो करोड़ दो लाख 71 हजार रुपए की राशि जारी की है।

खाद्य एवं आपूर्ति

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना : इस योजना के तहत गरीब परिवार की महिलाओं को 9 लाख 19 हजार 264 मुफ्त गैस कनेक्शन दिये गये हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली : उचित मूल्य की 9 हजार 400 दुकानों पर उपभोक्ताओं को राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है।

एक राष्ट्र - एक राशन कार्ड : इसके तहत अब किसी भी राशन डिपो से अपना आधार कार्ड दिखाकर राशन लेने की सुविधा दी गई है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनाः देश में कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थियों को राशन प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत 1.38 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मुफ्त राशन दिया गया।

श्रमिक कल्याण

प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना

इस योजना में 18 से 40 वर्ष की आयु वाला कोई भी असंगठित श्रमिक शामिल हो सकता है। यह योजना कार्यशील आयु के दौरान छोटी सस्ती राशि के मासिक योगदान पर 60 वर्ष की आयु के उपरांत 3,000 रुपए की एक निश्चित पेंशन प्रदान करती है।

उच्चतर शिक्षा

नई शिक्षा नीति-2020 : इसके तहत 2030 तक लड़कियों का उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 50 प्रतिशत से अधिक करने का लक्ष्य रखा गया है। कक्षा नौवीं से 12वीं के सभी सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का प्रावधान किया गए।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना : प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलता है जिन्होंने दसवीं और बारहवीं तक पढ़ा हो या फिर बीच में ही स्कूल छोड़ दिया हो। 5 साल तक प्रशिक्षकों को परीक्षण दिया जाता है।

राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना : इस योजना के अंतर्गत जिला शिक्षुता एवं आत्मनिर्भर समिति का गठन किया गया है। जिसके तहत प्रत्येक माह में जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया जाता है ताकि जिला/स्थानीय स्तर पर शिक्षुता / रोजगार उद्यमिता को बढ़ावा मिल सके।

पी.एम.श्रीः पी.एम.श्री की परिकल्पना 21वीं सदी की मांगों को पूरा करने वाले मॉडल स्कूलों के लिए की गई। इस के तहत हर ब्लॉक में दो स्कूल, (एक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और एक प्राथमिक विद्यालय) खोले जाएंगे।

सिविल विमानन

राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति

हिसार हवाई अड्डे के यात्री टर्मिनल का उद्घाटन 15 अगस्त, 2018 को कर दिया गया है। करनाल हवाई अड्डे को घरेलू हवाई अड्डा बनाने के लिए 28 एकड़ दो कनाल 4 मरले भूमि की पहचान कर ली गई है तथा इसकी खरीद के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

फरीदाबाद में 325 करोड़ रुपए की लागत से सड़क तंत्र सहित विभिन्न बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं का कार्य पूरा किया जा चुका है, जिससे जनता को बहुत लाभ मिल रहा है।

विभिन्न विभागों में कार्य करने हेतु 534 कंडक्टरों को शॉर्टलिस्ट किया गया। 896 लोगों को 5 मई, 2023 को शॉर्टलिस्ट किया गया था। मुख्यमंत्री की ओर से सभी उम्मीदवारों को ऑनलाइन नियुक्ति पत्र भेजे गए।

समावेशी शिक्षा से सशक्तिकरण

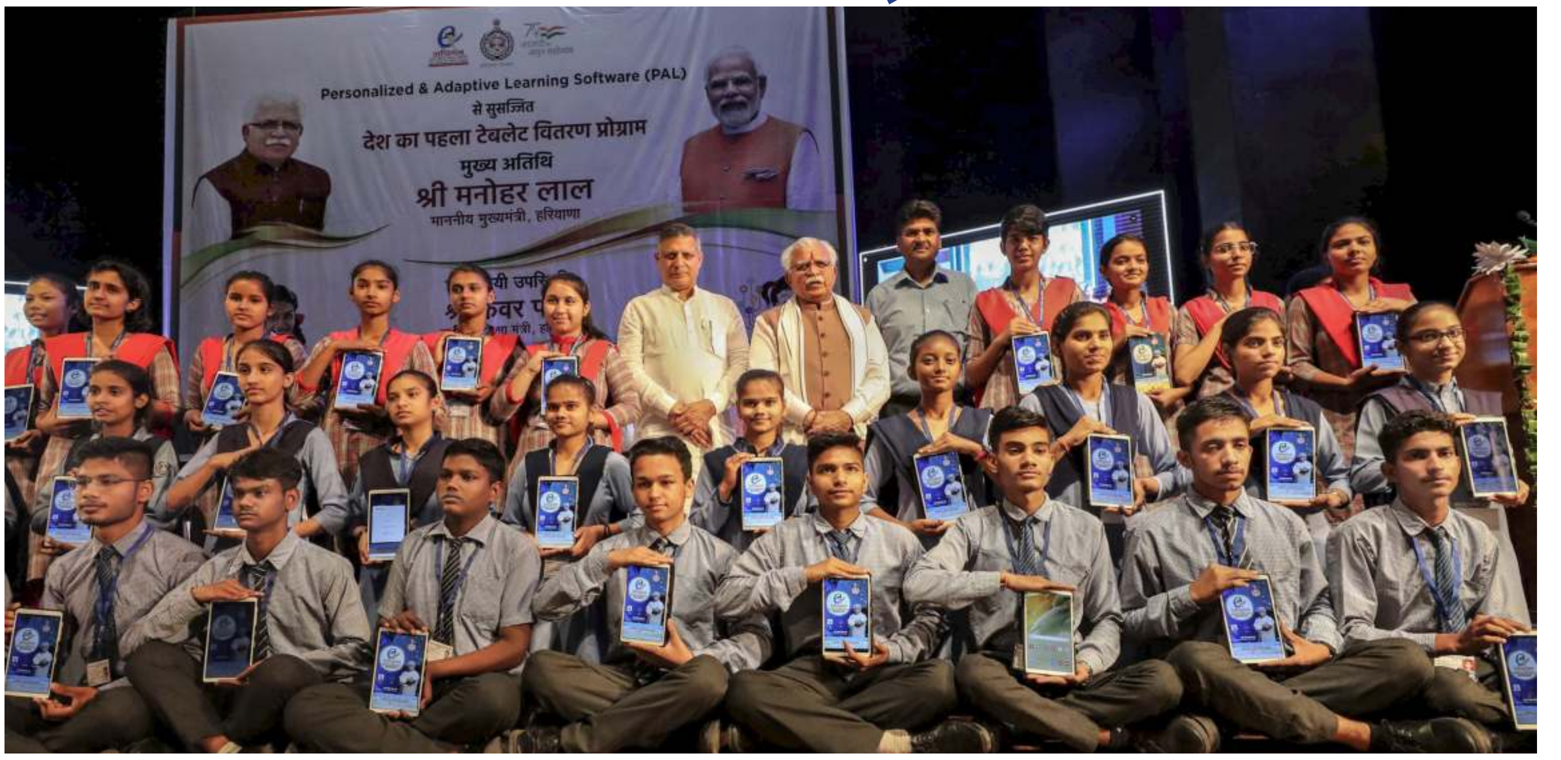

हरियाणा सरकार लगातार शिक्षा सुधार को लेकर अनेक प्रयास कर रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने की नई पहलें शुरू की गई है। बेटियों की उच्च शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है और लड़कियों के नए कॉलेज खोले गए हैं। रोज़गारपरक शिक्षा को प्राथमिकता देकर युवाओं को प्लेसमेंट के माध्यम से नौकरी के साथ-साथ आत्मनिर्भर भी बनाया जा रहा है। इच्छुक युवाओं को विदेश में रोज़गार उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।

कंवर पाल, शिक्षा मंत्री, हरियाणा

संगीता शर्मा

शिक्षा विकास की पहली सीढ़ी है और शिक्षा से परिवार, गांव, प्रदेश व देश निरंतर आगे बढ़ता है। इसलिए युवाओं को गुणात्मक, नैतिक व रोज़गारपरक शिक्षा को ग्रहण करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। इसके बलबूत ही वह आगे बढ़कर राष्ट्रहित में अपना योगदान दे सकते हैं। यह सब सार्थक बनाने पर देश व प्रदेश सरकार का अहम भूमिका होती है। केंद्र सरकार की वर्तमान सरकार ने अपने नौ साल के कार्यकाल में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 लागू करके भी बहुत सराहनीय काम किया है। हरियाणा सरकार भी इस नीति को हरियाणा में प्रमुखता से लागू कर रही है। गुरुग्राम स्थित श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय ऑन द जॉब ट्रेनिंग को सर्वोपरि लेकर चलता है ताकि विद्यार्थी पढ़ाई के साथ साथ फील्ड में काम सीखे और सीधा इंडस्ट्री के साथ जुड़े। इससे उनको पढ़ाई के साथ-साथ कमाई का भी अवसर मिलता है।

शिक्षा से वंचित न रहें युवा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में जो कहा गया है कि पूर्व प्राथमिक से 12वीं कक्षा तक के सभी विद्यार्थियों के लिए शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच और उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी, इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हरियाणा सरकार ने विद्यालयों का दर्जा बढ़ाने का निर्णय लिया है। परिवार पहचान पत्र में 6 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के हर बच्चे की मैपिंग स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा की जा रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी बच्चा शिक्षा के अवसरों से वंचित न रहें। सुपर 100 और बुनियाद कार्यक्रम के केंद्रों को बढ़ाने की भी योजना है।

पी.एम.श्री योजना

पी.एम.श्री की परिकल्पना 21वीं सदी की मांगों को पूरा करने वाले मॉडल स्कूलों के लिए की गई। इस के तहत हर ब्लॉक में दो स्कूल, (एक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और एक प्राथमिक विद्यालय) खोले जाएंगे और उन्हें पी.एम.श्री मॉडल संस्कृति स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020

इसके तहत 2030 तक लड़कियों का उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 50 प्रतिशत से अधिक करने का लक्ष्य रखा गया है। कक्षा 9वीं से 12वीं के सभी सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का प्रावधान किया गया है। राज्य में 4,081 आंगनवाड़ियों को प्ले स्कूल में परिवर्तित किया गया है। अगले दो वर्षों में 4,000 और प्ले स्कूल खोले जाएंगे।

राज्य सरकार ने पांच किलोमीटर के दायरे में एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल का प्रावधान करने का निर्णय लिया है, ताकि बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए अधिक दूरी तय न करनी पड़े। प्रदेश में मिशन मेरिट के कारण पढ़ाई का ऐसा वातावरण बना है जिससे अब युवा शिक्षा को पहले से अधिक महत्व दे रहे हैं। सरकार के पास गांवों में लाइब्रेरी बनाने की इतनी अधिक मांग आ रही है, इसलिए सरकार ने अब पहले चरण में बड़े गांवों लाइब्रेरी खोलने का निर्णय लिया है। आने वाले समय में 1,200 ई लाइब्रेरी प्रदेश के विभिन्न गांव में खोली जाएंगी।

20 जिलों के 113 स्कूल होंगे अपग्रेड

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वर्ष 2023-24 के बजट अभिभाषण में प्रदेश में हाई स्कूलों को सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में अपग्रेड करने की प्रमुख घोषणा को पूरा करते हुए प्रदेशभर में 113 हाई स्कूलों को अपग्रेड करने की मंजूरी प्रदान की है। हरियाणा सरकार द्वारा नियमों में छूट/राहत देते हुए पहले चरण में इन स्कूलों को अपग्रेड करने के उपरांत चरणबद्ध तरीके से अन्य स्कूलों को भी अपग्रेड किया जाएगा।

प्रदेशभर में जिन स्कूलों में 9वीं और 10वीं कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 80 या इससे अधिक है, एक एकड़ या इससे अधिक भूमि उपलब्ध है तथा सबसे निकटतम सीनियर सेकेंडरी स्कूल तीन किलोमीटर या इससे अधिक दूरी पर है, ऐसे सभी स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप 12वीं कक्षा तक सभी विद्यार्थियों के लिए शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। 20 जिलों के 64 खण्डों में कुल 113 हाई स्कूलों को सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में अपग्रेड किया जाएगा।

उच्चतर शिक्षा

राज्य में उच्चतर शिक्षा प्रणाली में हाल के वर्षों में प्रभावशाली सुधार आया है और यह आने वाले वर्षों में भी जारी रहने की उम्मीद है। हरियाणा में उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात वर्तमान में 32 प्रतिशत है। सरकार ने वर्ष 2030 तक इसे 40 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। वर्ष 2023-24 में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में विद्युत वाहन, मैन्युफै• रिंग, एविएशन, फार्मेसी और ग्रीन टेक्नोलॉजीज में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

भगत फूल सिंह कन्या विश्वविद्यालय, खानपुर कलां, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक में केजी से पीजी स्कीम के तहत दाखिले किये हैं। अन्य कालेजों में हिंदी माध्यम से कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रनिक्स और कॉम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में शुरू किया गया है।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

प्रदेश के 42 हजार 388 उम्मीदवारों का पंजीकरण किया गया। जिनमें से 39 हजार 627 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण और 7 हजार 430 को रोज़गार उपलब्ध करवाया गया।

राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना

इस योजना में पोर्टल के माध्यम से ही प्रशिक्षुओं का पंजीकरण एवं प्रतिष्ठानों का पंजीकरण होता है। हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना के तहत अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर लगभग 18,648 प्रतिष्ठानों (सरकारी व निजी) में 1.44 लाख प्रशिक्षु नियुक्त किए गए है।

युवाओं का कौशल विकास

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप इंडस्ट्री की मांग पर आधारित गुरुग्राम स्थित श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में कोर्सों का संचालन किया जा रहा है। हरियाणा और देश के युवाओं को कुशल बनाने की दिशा में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस बार कोर्सों की संख्या बढ़कर 42 हो गई है।

दक्षिणी हरियाणा में नहीं रहेगा जल संकट

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम में जताई प्रतिबद्धता

दक्षिणी हरियाणा में टेल तक पानी पहुंचाने के लिए विगत साढ़े आठ वर्षों में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। जल संकट के स्थायी समाधान के प्रयास जारी हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महेंद्रगढ़ के गांव बलाहा कलां में आयोजित जन संवाद कार्य म में कहा कि जल संरक्षण की दिशा में अनेक सराहनीय कदम उठाए गए हैं। ग्रामीण भी जल स्तर को उठाने के लिए जल संचय करें व फसल विविधिकरण अपनाएं।

उन्होंने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि पानी के संकट को खत्म करने के लिए क्षेत्र में जरूरत अनुरूप नहर की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने गांव गोद, बलाहा कलां व खुर्द द्वारा जमीन उपलब्ध कराने पर करीब चार किलोमीटर की नहर बनाने की व्यवस्था करने की बात कही। साथ ही नलवाटी क्षेत्र में पानी की समस्या का स्थायी समाधान करने के निर्देश भी सम्बंधित अधिकारियों को दिए।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का शिक्षा पर पूरा फोकस है। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को राजकीय स्कूलों में गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान की जा रही है। जहां स्कूल अपग्रेड करने की आवश्यकता होगी वहां नियमों के अनुरूप अपग्रेड किये जायेंगे। गांव खोरियावास में नया मेडिकल कॉलेज बन रहा है, अगले साल तक स्वास्थ्य सेवा के रूप में मेडिकल कॉलेज की सौगात महेंद्रगढ़ को मिल जाएगी। लॉजिस्टिक हब भी महेंद्रगढ़ जिला के बसिरपुर में बनेगा तथा खुडाना गांव में नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित होगा, जिससे रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गांव बलाहा कलां में 5.31 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचसी) का उद्घाटन किया। इससे बलाहा कलां के साथ-साथ आसपास के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी।

नशा रोकथाम में सहभागी बनें ग्रामीण-मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा रोकथाम के लिए महेंद्रगढ़ जिला में विशेष अभियान चलाया जाएगा। पुलिस अधीक्षक वि ंत भूषण को निर्देश दिए कि राजस्थान सीमा से सटे होने के कारण इस जिला में एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। यह भी मॉनिटरिंग की जाए कि कोई भी यदि नशीले पदार्थों की आपूर्ति करता है तो उसकी सूचना प्रशासन को दें ताकि युवाओं को भटकाव से रोका जा सके।

- संवाद ब्यूरो

हरियाणा कौशल रोजगार निगम

कौशल रोजगार निगम की ओर से 108 एनालिटिकल एसोसिएट्स, 55 आयुष योग सहायक, 34 डाटा एंट्री ऑपरेटर, 92 फायरमैन/फायर ड्राइवर, 57 जुनियर इंजीनियर व 60 लैब सुपरवाइजर को नियुक्ति पत्र भेजे गए।

राज्य भंडारण निगम राज्य में 115 गोदामों का संचालन कर रहा है, जिनकी कुल औसत भंडारण क्षमता 18.74 लाख मीट्रिक टन है। वित्तीय वर्ष 2020-21 का 8,23,05,400 रुपये सहित कुल 12,63,15,817 रुपए का लाभांश हुआ है।

समृद्ध होता एमएसएमई

ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की नीतियों को प्राथमिकता के आधार पर लागू किये जाने पर काम चल रहा है। 'एग्री-बिजनेस एंड फूड प्रोसेसिंग पोलिसी 2018' इसी तरह की योजना है। इसके तहत कुल 57 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें सही पाए गए 42 आवेदनों पर उनके प्रोजेक्टस को स्वीकृति दे दी गई। इन प्रोजेक्टस में करीब 570 करोड़ रुपए का निवेश करने की प्रक्रिया है जिसमें से 120 करोड़ रुपए का अनुदान स्वीकृत किया गया है।

राज्य में इस वक्त 9 लाख 70 हजार से ज्यादा एमएसएमई हैं जिनमें से 9 लाख 53 हजार माइक्रो यूनिटस हैं। राज्य में एमएसएमई के तहत 19.06 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं जो कि प्रदेश के लिए गर्व की बात है।

वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट

राज्य सरकार द्वारा स्टार्टअप शुरू करने वाले युवा उद्यमियों की तरह 'पदमा' (प्रोग्राम टू एक्सीलेरेट डिवलेपमैंट फॉर एमएसएमई एडवान्समैंट) में भी वेंचर कैपिटल फंड स्थापित किया जाएगा ताकि वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट के तहत अधिक से अधिक युवा इंटरप्रेन्योर बन सकें।

प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार की 'पदमा' योजना के तहत 'वन ब्लॉक-वन प्रोडक्ट' पहल शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य क्लस्टर दृष्टिकोण का लाभ उठाकर और संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देकर ब्लॉक स्तर पर सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि हाल ही में पेश किए गए बजट में भी अगले 5 वर्षों में 'पदमा' के लिए 1,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए हैं जिससे डिजाइनिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम जैसे नए इनोवेटिव इंसेंटिव पेश किए जाएंगे।

युवाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए इन्क्यूबेशन केंद्रों की स्थापना की जाएगी और बैंकों, वित्तीय संस्थानों और उद्यम पूंजी निधियों से ऋण की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी, वहीं 'पदमा' के तहत विशेषकर ग्रामीण युवाओं को इंटरप्रेन्योर बनाया जाएगा। 'पदमा' के तहत उद्योग लगाने हेतु करीब दो दर्जन स्थानों की पहचान कर ली गई है, बाकी ब्लॉक में जगहों को अंतिम रूप देकर लोगों को उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

मेट्रो का विस्तार

दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन द्वारा प्रदेश में पांच परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है जिनमें हुडा सिटी सेंटर-रेलवे स्टेशन-सेक्टर 22-साइबर सिटी, फरीदाबाद तथा गुरुग्राम के मध्य मेट्रो कनेक्टिविटी, दक्षिण पेरीफरी रोड तथा उत्तरी पेरीफरी रोड के मध्य, बाढसा से द्वारका के मध्य, बहादुरगढ़ से सांपला के मध्य मेट्रो कनेक्टिविटी की परियोजनाएं शामिल हैं।

हुडा सिटी सेंटर-रेलवे स्टेशन-सेक्टर 22-साइबर सिटी तक मेट्रो रेल कनेक्टिविटी के लिए प्रारूप विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को मंजूरी दे दी गई। इस मेट्रो रेल लाइन की कुल लंबाई 31.11 किलोमीटर है और इसमें 25 स्टेशन और छह इंटरचेंज स्टेशन होंगे। इस मेट्रो लाइन के निर्माण पर अनुमानित लागत 5126 करोड़ रुपये होगी और इसके वर्ष 2023 में चालू किए जाने की संभावना है। इस मार्ग पर जिन मेट्रो स्टेशनों का प्रस्ताव किया गया है, उनमें हुडा सिटी सेंटर, सेक्टर 45, साइबर पार्क, सेक्टर 46, सेक्टर 47, सेक्टर 48, टेक्नोलॉजी पार्क, उद्योग विहार फेज 6, सेक्टर 10, सेक्टर 37, बसई, सेक्टर 9, सेक्टर 7, सेक्टर 4, सेक्टर 5, अशोक विहार, सेक्टर 3, कृष्णा चौक, पालम विहार एक्सटेंशन, पालम विहार, सेक्टर 23 ए, सेक्टर 22, उद्योग विहार फेज-4 और 5 तथा साइबर सिटी शामिल है।

श्रमिक कल्याण

श्रम विभाग के मुताबिक जनवरी माह में अधिकारियों द्वारा 377 दावों के मामलों पर निर्णय लिए गए। महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर हिसार, रोहतक, फरीदाबाद, धारूहेड़ा, चरखी दादरी में पांच पूर्णकालिक श्रम कल्याण सेंटर खोले गए। सेंटर्स में महिलाओं के लिए लाइब्रेरी, बुनाई और सेवा के साथ गेम्स, और अन्य मनोरंजक गतिविधियां भी शुरू की गई हैं। कुल 31 असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के सर्किल में 176 शिकायतों का निपटारा किया गया। औद्योगिक विवादों के अंतर्गत बंदी, हड़ताल और छंटनी के मामलों में सुलह अधिकारियों द्वारा 32 मामलों का निपटान किया गया। किसी भी श्रमिक की छंटनी नहीं की गई तथा किसी ट्रेड यूनियन का नया रजिस्ट्रशन नहीं हुआ।

कुल 515 कारखानों की रजिस्ट्रेशन की गई और किसी भी फैक्ट्री की रजिस्ट्रेशन रद्द नहीं हुई। कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 के तहत श्रमिकों को पांच करोड़ से अधिक का मुआवज़ा दिया गया। कुल 377 क्लेम केसेस का निपटारा किया गया। इस साल फरवरी 2023 में सुलह अधिकारियों द्वारा 47 औद्योगिक मामलों का निपटारा किया गया। श्रम कानूनों के अंतर्गत 509 निरिक्षण किए गए। विभिन्न मज़दूरी कानूनों के अंतर्गत 498 क्लेम केस सेटल किये गए।

वैश्विक पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हरियाणा

हरियाणा सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की मदद से निरंतर प्रयासरत है। अब तक हुए प्रयासों का परिणाम है कि हरियाणा का नाम वैश्विक स्तर पर लिया जा रहा है। देश विदेश के लोगों में इस पवित्र धरती का भ्रमण करने की व्याकुलता बढ़ी है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की ओर से अनेक नीतियां शुरू की गई हैं।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दूरदर्शी सोच से राज्य में पर्यटन क्षेत्र में कई गुणा विकास हुआ है। हरियाणा के अरावली पर्वत श्रृंखला के गुरुग्राम और नूंह जिले में लगभग 10,000 एकड़ भूमि पर दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क विकसित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। आगंतुक यहां सफारी राईड्स, मनोरंजन जोन, इको विलेज, प्रकृति की सैर, भोजन व मनोरंजन जैसी गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। यह पार्क अनुमानित पांच साल में बनकर तैयार होगा जिसमें चरणबद्ध तरीके से काम होगा। सुलतानपुर झील अंतराष्ट्रीय पहचान बना चुकी है जहां शीतकाल में प्रवासी पक्षी आवास के लिए आते हैं। झज्जर की भिंडावास झील भी प्रवासी पक्षियों की आरामगाह के रूप में प्रसिद्ध हो चुकी है।

हरियाणा एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का केन्द्र है जो पर्यटकों एवं आगंतुकों को वैदिक काल का अनुभव करवाता है। राज्य के अपने समृद्ध रीति-रिवाज और परंपराओं के साथ ही लोकगीत हैं जो अपनी महान सांस्कृतिक विरासत को भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जन-जन तक पहुंचा रहे हैं।

राज्य सरकार ने हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने और ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से 'होम स्टे' नीति बनाई है। इसके तहत पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिलेगा।

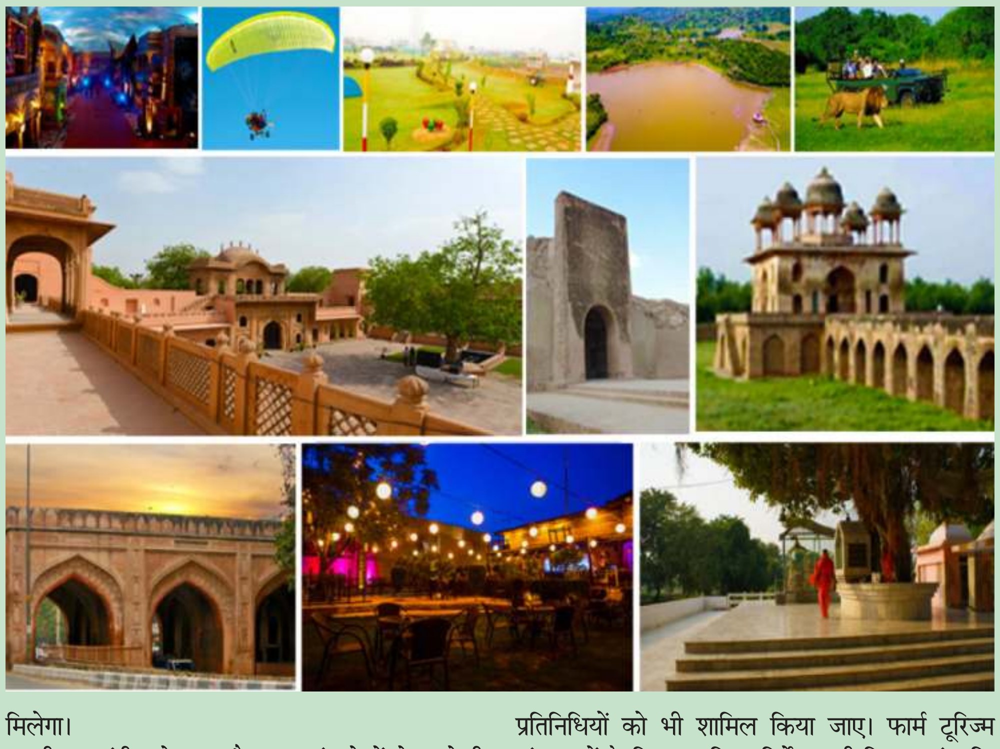

गीता जयंती महोत्सव और सूरजकुंड मेलों से पहले ही हरियाणा ने दुनियाभर में अमिट छाप छोड़ी है। इसके अलावा साहसिक खेलों के लिए पंचकूला के टिक्कर ताल, मोरनी हिल्स क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकसित किया जा रहा है।

मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि संबंधित अधिकारियों से कहा कि पर्यटन की दृष्टि से कंट्रोल्ड क्षेत्रों की पहचान करने व विकास योजनाएं तैयार करने के लिए राज्य और जिला स्तरीय समितियों में पर्यटन विभाग के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए। फार्म टूरिज्म संचालकों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए जाएं ताकि वे अपने फार्म टूरिज्म हाउस का पंजीकरण सरलता से कर सकें।

राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण खेलों, फार्म राइड्स, कृषि, क्षेत्रीय कला एवं संस्कृति जैसी गतिविधियों सहित नए फार्म टूरिज्म हाउस खोलने की योजना पर भी काम शुरू किया गया है। फार्म हाउस खोलने के लिए विशिष्ट क्षेत्र का पंजीकरण करते समय बैंक्वेट, रेस्टोरेंट और मैरिज हॉल आदि के लिए भूमि के दुरुपयोग को रोकने के लिए फील्ड सर्वे अनिवार्य रूप से किया जाना अनिवार्य है। कृषि जोन में फार्म टूरिज्म हाउस खोलने के लिए पंजीकरण से पहले भूमि उपयोग परिवर्तन (सीएलयू) प्रमाण पत्र अनिवार्य दस्तावेज है। इसलिए फार्म मालिकों द्वारा सक्षम राजस्व प्राधिकरण से सीएलयू प्रमाण पत्र की आवश्यकता के संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी हों।

राज्य की पर्यटन नीति का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना है जो रोजगार सृजन के लिए एक ग्रोथ इंजन के रूप में कार्य करेगा। इस नीति के माध्यम से हरियाणा को एक आदर्श पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है।

-मनोज प्रभाकर

पर्यटन को गति देगा एमआईसीई मॉडलः कंवरपाल

हरियाणा में एमआईसीई मॉडल (मिटिंग, इन्सेंटिव, कान्फ्रेंस एण्ड एग्जीबिशन) से पर्यटन क्षेत्र को अग्रणी बनाने की अपार सम्भावनाएं है। विरासत एवं पर्यटन मंत्री कंवर पाल ने कहा कि एमआईसीई मॉडल से पर्यटन को बढावा देने के लिए बड़े स्तर पर लोगों को एकत्रित किया जा सकता हैं। एमआईसीई पर्यटन को बढावा देने और आर्थिक क्षेत्र को मजबूत करने तथा रोजगार को बढ़ावा देने का सरकार का दूरदर्शी विजन है। इसके तहत हरियाणा के पंचकुला, यमुनानगर, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार और महेंद्रगढ़ में पर्यटन को विकसित किया जाएगा। इस प्रकार हरियाणा में एमआईसीई से पर्यटन को विकसित करने के लिए वैश्विक व्यापार को ओर अधिक बल मिलेगा।

प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत 6,260 गांवों की 23,93,366 सम्पतियों के भू-स्वामियों को पंजीकृत टाईटल डीड वितरित कर दी गई हैं।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 1.38 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मुफ़्त राशन दिया गया।

सेहत को लेकर संजीदगी

हरियाणा सरकार सेहत के मामले में शुरू से संजीदगी रही है। लोगों को हर समय सहज व सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों इसके लिए खूब कार्य हुआ है। न केवल ढांचागत विकास हुआ है बल्कि चिकित्सा क्षेत्र की मजबूती के लिए मेडिकल व पैरामेडिकल स्टाफ की भी भर्ती की गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कितने जागरूक एवं गंभीर हैं इस बात का अंदाजा कोरोना काल में उनकी अथक मेहनत से लगा लिया गया था। उन्होंने दिन-रात एक कर सेनापति की तरह कोरोना से जंग लड़ी थी।

स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के सहयोग से अनेक ऐसी योजनाओं को अमलीजामा पहनाया है जिससे ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के मरीजों को निरंतर लाभ मिल रहा है।

ईएसआई स्वास्थ्य केंद्र

ईएसआई हेल्थ केयर, हरियाणा प्रदेशभर में 7 ईएसआई अस्पतालों (4 ईएसआईएस और 3 ईएसआईसी), 3 आयुर्वेदिक इकाइयों, 1 मोबाइल और 85 डिस्पेंसरी के माध्यम से संगठित क्षेत्रों में काम करने वाले 25 लाख बीमित व्यक्तियों और उनके परिवार के सदस्यों को व्यापक चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है।

करनाल, रोहतक, झाड़ली, गन्नौर, मुलाना, घरौंडा, फरुखनगर, कोसली, साहा, छछरौली, पटौदी, भूना, चरखी दादरी और उकलाना मंडी में 14 नई ईएसआई डिस्पेंसरी खोली जाएंगी।

रोहतक, पटौदी और झाड़ली के लिए ईएसआई डिस्पेंसरी के लिए ईएसआई निगम, नई दिल्ली से सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। चरखी दादरी, रोहतक और झाडली ईएसआई डिस्पेंसरी के भवनों का कब्जा ले लिया गया है।

कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई), हरियाणा संगठित क्षेत्र के लिए एक अंशदायी सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसमें 10 या उससे अधिक कर्मचारियों, जो 21 हजार रुपये प्रति माह वेतन प्राप्त करते हैं, वाली इकाइयों को कवर किया जाता है। राज्य में ईएसआई लाभार्थियों के लिए कैशलेस आधार पर सेकेंडरी स्तर की चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए 109 निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है।

मानेसर में 500 बिस्तरों के नए ईएसआई अस्पताल के लिए ईएसआईसी द्वारा 8.70 एकड़ भूमि खरीदी गई है। गुरुग्राम में 163 बिस्तरों से 500 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल के विस्तार के लिए 18793.27 वर्ग मीटर (4.64 एकड़) भूमि की पहचान की गई है। राई में ईएसआई डिस्पेंसरी का निर्माण सेक्टर 38, फेज-2, औद्योगिक एस्टेट राई में किया जाएगा। गन्नौर ब्लॉक के बरही में ईएसआई डिस्पेंसरी स्थापित करने की योजना को ईएसआई निगम द्वारा अनुमोदित किया गया है।

बेहतर चिकित्सा के लिए ढांचागत विकास

विभिन्न जिलों में मेडिकल कॉलेज, नागरिक अस्पताल के अलावा गांव स्तर पर भी बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। जिला अस्पतालों में एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड और एमआरआई मशीनों को उपलब्ध करवाया है। प्रदेश में 4 कैथ लैब चल रही हैं। 162 पीएचसी को तोड़कर नया बनाया जाएगा। रोहतक मेडिकल कॉलेज में लिवर व किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।

ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं के सुधार के लिए नए अस्पताल बनाए जाएंगे। जहां भी पुरानी बिल्डिंग है, उसे तोड़कर नया बनाया जाएगा। प्रदेश में सरकारी अस्पताल की मैपिंग करवाई जा रही है। विस्तृत रिपोर्ट के बाद लोगों की जरूरत के अनुसार नए अस्पताल बनाए जाएंगे। हाल ही में प्रदेश के 17 जिलों में 232 करोड़ रुपए की लागत के 46 स्वास्थ्य संस्थानों का लोकार्पण किया गया। प्रदेश में नए मेडिकल कॉलेज खोलने से एमबीबीएस सीटों की संख्या बढ़कर 1900 हो गई है, जो पहले 750 थी। प्रदेश को आने वाले समय में 7 नए मेडिकल कॉलेज मिलेंगे, इनके बनने के बाद एमबीबीएस सीटों की संख्या 3 हजार से अधिक हो जाएगी।

ऑनलाइन प्रमाण पत्र: प्रदेश में अब निजी अस्पतालों को निर्धारित समय पर सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। उन्हें ऑनलाईन एमपैनलमेंट प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा। दवा संस्थानों के नियमित निरीक्षण के लिए खाद्य एवं औषध प्रशासन विभाग द्वारा भी एक साफ्टवेयर लांच किया गया है।

चिरायु योजना

केन्द्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य लाभ दिया जा रहा है। हरियाणा में 15,51,798 परिवार इस योजना में कवर हो रहे थे। इनमें से लगभग 9 लाख परिवार इस योजना का लाभ उठा रहे थे। चिरायु योजना लागू करने से प्रदेश में अब लगभग 20 लाख परिवार और इस योजना में जुड़ गए हैं। राज्य सरकार ने लगभग 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

सरकार ने इस योजना का लाभ अधिक परिवारों को देने के लिए बीपीएल की आय सीमा को बढाकर 1.80 लाख रुपए कर दिया। अब इस योजना के तहत लगभग 29 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इसको लेकर आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया तेजी से की जा रही है। जिन परिवारों के कार्ड नहीं बने है उनके कार्ड बनाये जा रहे हैं। इसके लिए स्वास्थ्य केन्द्रों पर अतिरिक्त काउंटर बनाये गए हैं।

चिरायु योजना के तहत 44 लाख से ज्यादा नये गोल्डन कार्ड बने। चिरायु योजना शुरू करने से पहले आयुष्मान भारत योजना में प्रदेश के 28,89,287 व्यक्तियों के गोल्डन कार्ड बनाए गए थे। चिरायु योजना के तहत प्रदेश में कुल 715 अस्पताल सूचीबद्ध हैं, जिनमें 539 निजी अस्पताल और 176 सरकारी अस्पताल शामिल हैं।

आयुष सेवाओं को बढ़ावा

हरियाणा में आयुष शिक्षा एवं स्वास्थ्य देखभाल की आयुष प्रणालियों के श्रेष्ठतम विकास को सुनिश्चित करने के लिए आयुष विभाग को स्वास्थ्य विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग से अलग किया गया है।

निदेशालय आयुष हरियाणा के तालमेल से भारत सरकार द्वारा जिला पंचकूला में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान और जिला झज्जर के गांव देवरखाना में एक स्नातकोत्तर योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा शिक्षा व अनुसंधान संस्थान स्थापित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार जिला हिसार, गांव मैयड़ में 50 बिस्तर का संपूर्ण आयुष अस्पताल, जिला नूह, गांव अकेड़ा में राजकीय यूनानी कालेज व अस्पताल तथा जिला अम्बाला, गांव चांदपुरा में राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज व अस्पताल की स्थापना हेतु राज्य सरकार को सहयोग कर रही है। राज्य सरकार द्वारा श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र स्थापित किया गया है।

गर्मी व लू से बचाव

मौसम विभाग ने लू से बचने के लिए अलर्ट जारी किया है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से भी एडवाइजरी जारी हुई है। खासकर धूप में घूमने वाले लोगों, खिलाड़ियों, बच्चों, बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों को लू लगने का डर ज्यादा रहता है। लू लगने पर उसके इलाज से बेहतर है कि पहले ही सावधानी बरती जाए। लू से बचाव के लिए स्थानीय मौसम संबंधी खबरों के लिए रेडियो- टीवी अथवा समाचार पत्र से जानकारी लेते रहें।

लू से बचने के उपाय

» गर्मी में हल्के रंग के ढीले सूती कपड़े पहनें।
» सिर ढककर रखें, कपड़े, हैट अथवा छतरी का उपयोग करें।
» चश्मा पहनकर बाहर जाएं। चेहरे को कपड़े से ढक लें।
» कभी भी खाली पेट घर से नहीं निकलें।
» पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं-भले ही प्यास न लगी हो।
» ओआरएस, लस्सी, तोरानी (चावल का मांड) नींबू पानी, छाछ आदि का सेवन करें।
» लू के समय प्याज जरूर खाना चाहिए। प्याज को सलाद के रूप में खाएं।
» आम पन्ना गर्मियों का बेहद लोकप्रिय ड्रिंक है।
» ज्यादा पसीना आया हो तो फौरन ठंडा पानी न पीएं। सादा पानी भी धीरे-धीरे करके पीएं।
» रोजाना नहाएं और शरीर को ठंडा रखें।
» घर को ठंडा रखने की कोशिश करें।
» बाजार में बिक रहे कटे-फटे फल तो बिलकुल न खाएं।

लक्षण

» लू लगने पर शरीर में गर्मी, खुश्की और थकावट महसूस होने लगती है।
» मसल्स में खिंचाव लगता है, शरीर टूटने लगता है और प्यास बढ़ जाती है।
» कई बार बुखार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जैसे कि 105 या 106 डिग्री फॉरेनहाइट।
» ब्लड प्रेशर लो हो जाता है और लिवर-किडनी में सोडियम पोटैशियम का बैलेंस बिगड़ जाता है।
» ब्रेन या हार्ट स्ट्रोक की स्थिति बन सकती है। वक्त पर इलाज न मिले तो जान जा सकती है।
» बेहोशी आना, तेज बुखार, सांस लेने में तकलीफ, उलटी आना, चक्कर आना, दस्त, सिरदर्द, शरीर टूटना, बार-बार मुंह सूखना और हाथ-पैरों में कमजोरी आना या निढाल होना भी लू लगने के लक्षण हो सकते हैं। काफी पसीना आ सकता है या एकदम पसीना आना बंद भी हो सकता है।

लू लगने पर क्या करें?

» सबसे पहले मरीज को ठंडी और छायादार जगह में बिठाएं या लिटाएं। कपड़े ढीले कर दें, पानी पिलाएं और ठंडा कपड़ा उसके शरीर पर रखें।
» शरीर के तापमान को कम करने की कोशिश करें। लू लगने पर ऐसा करना सबसे जरूरी है।
» लगातार तरल पदार्थ देकर उसके शरीर में पानी की कमी न होने दें। नमक व चीनी मिला हुआ पानी, शर्बत आदि दें।
» उसके हाथ-पैरों की हल्के हाथों से मालिश करें। तेल न लगाएं।
» गुलाब जल में रुई भिगोकर आंखों पर रखें। फिर भी आराम न आए तो डॉक्टर के पास ले जाएं।

लू लगने पर खान-पान

» बेल या दूसरी तरह के शर्बत और जौ का पानी दें। खिचड़ी दे सकते हैं।
» तलवों, हथेलियों व माथे पर चंदन का लेप और सिर पर मेहंदी लगाएं।
» बाहर का खाना न खाएं। घर में भी परांठा, पूड़ी-कचौड़ी आदि तला-भुना न खाएं।
» नींबू पानी और इलेक्ट्रॉल पीते रहें। शुगर के मरीज बिना चीनी का शर्बत और ठंडाई लें।
» आधा दूध और आधा पानी मिलाकर लस्सी पीएं।

नदी आई है

यदि हमारे बस में होता,
नदी को उठा घर ले आते।
अपने घर के ठीक सामने,
उसको हम हर रोज बहाते।
कूद-कूद कर उछल-उछल कर,
हम मित्रों के साथ नहाते।
कभी तैरते कभी डूबते,
इतराते गाते मस्ताते।
'नदी आई है' आओ नहाने,
आमन्त्रित सबको करवाते।
सभी उपस्थित भद्रजनों का,
नदियों से परिचय करवाते।
यदि हमारे मन मे आता
झटपट नदी पार कर जाते।
खड़े-खड़े उस पार नदी के
मम्मी मम्मी हम चिल्लाते।
शाम ढले फिर नदी उठाकर
अपने कन्धे पर रखवाते।
लाये जहां से थे हम उसको
जाकर उसे वहीं रख आते।
खड़े-खड़े उस पार नदी के
मम्मी-मम्मी हम चिल्लाते।
शाम ढले फिर नदी उठाकर
अपने कन्धे पर रखवाते।
लाए जहां से थे हम उसको
जाकर उसे वहीं रख आते।
मेरे जैसे हो जाओ
नदी निकलती हैं पर्वत से,
मैदानों में बहती हैं।
और अन्त मे मिल सागर से,
एक कहानी कहती हैं।
बचपन में छोटी थी पर मैं,
बड़े वेग से बहती थी।
आंधी-तूफ़ान, बाढ़-बवंडर,
सब कुछ हंसकर सहती थी।
मैदानों में आकर मैंने,
सेवा का संकल्प लिया।
और बना जैसे भी मुझसे,
मानव का उपकार किया।
अन्त समय में बचा शेष जो,
सागर को उपहार दिया।
सब कुछ अर्पित करके अपने,
जीवन को साकार किया।
बच्चो शिक्षा लेकर मुझसे,
मेरे जैसे हो जाओ।
सेवा और समर्पण से तुम,
जीवन बगिया महकाओ।

-नरेंद्र वर्मा

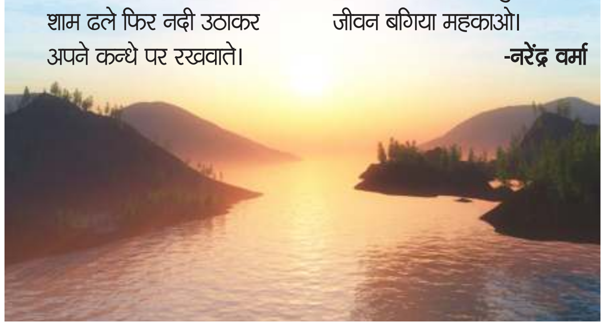

डॉ अमित अग्रवाल, भा.प्र.से. प्रबंध निदेशक, संवाद (सूचना जन संपर्क एवं भाषा विभाग) हरियाणा द्वारा हरियाणा सरकार के लिए कमरा नं. 314, दूसरी मंजिल, लघु सचिवालय, सेक्टर-1, पंचकूला से प्रकाशित।
कार्यालय : संवाद सोसायटी एससीओ 23, पहली मंजिल, सेक्टर 7, चंडीगढ़ फोन : 0172-2723814, 2723812 email : editorsamvad@gmail.com